

उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-2
संख्या-1506 /XXXI(2)/2014-90 (विविध)/2011
देहरादून : दिनांक 15 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

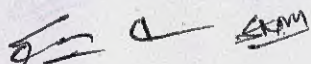
उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के समीक्षा अधिकारी संवर्ग की अन्तिम ज्येष्ठता सूची सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2549/XXXI(2)/2011-90(विविध)/2011, दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 द्वारा निर्गत की गयी थी। उक्त कार्यालय ज्ञाप के आपत्तियों के निराकरण विषयक प्रस्तर संख्या-34 में उ0प्र0 सचिवालय में चयन वर्ष 1991 के प्रतीक्षासूची से नियुक्त समीक्षाधिकारियों क्रमशः श्री संजीव कुमार शर्मा, श्री शैलेश कुमार पंत, श्री रावेन्द्र कुमार चौहान तथा श्री ललित मोहन आर्य की ज्येष्ठता के सम्बंध में तत्समय प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि इनकी ज्येष्ठता मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 संख्या-14296-97/2008 (CC 7870-7871) "योगेन्द्र कुमार पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

2- वर्तमान में विशेष अपील संख्या-256/1998 (नवीन संख्या-99/1999) "उत्तर प्रदेश राज्य बनाम योगेन्द्र कुमार पाल व अन्य" में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2007 एवं इस सम्बंध में योजित रिकाल प्रार्थना-पत्र संख्या-265023/2007 में पारित आदेश दिनांक 2.5.2008 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-14296-97/2008 "योगेन्द्र कुमार पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य" तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-14791-92/2008 "लाल बहादुर सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य" को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.02.2014 द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित कर निम्नवत आदेश पारित किये गये :-

An additional affidavit dated 27th August, 2013, has been filed on behalf of the State of U.P. - Respondent No.1.

Paragraph 7 and 8 of the afore-stated affidavit is being extracted hereunder:

7. That upon deliberation of the facts, especially in deference to the oral observations of this Hon'ble Court and further keeping in view the humanitarian aspects attached and the dependents of the persons who have continued in service on the basis of the order of the High Court, a view was taken in the said meeting that they may be considered to be allowed to remain in service but keeping in view of the implications with respect to different batches of the employees having joined on different dates in their regular appointments, the seniority of these petitioners including the others who are similarly placed (total 39), shall have to be considered after 16.03.2005, the date on which last 2001 batch of direct recruitment has taken place.



8. That the said view to place them in seniority from 16.03.2005 have been taken in view of the fact that three batches of direct recruitment (i.e. 1995 batch, 1999 batch and 2001 batch) have joined and the last joining took place on 16.03.2005. These 28 petitioners herein (Claimants) and other 11 who are not party to these proceedings, shall have to be placed before the said last appointee in view of the fact that it will become very difficult to reschedule and manage the seniority list. Even if the said efforts would be made, then that will create multiple causes of action for innumerable litigation by different parties claiming to be affected by the said rescheduling of the existing seniority list."

It was acknowledged by the learned counsel representing the State of Uttar Pradesh, during the course of hearing that the position expressed in paragraphs 7 and 8 relates to such of the appellants who have been appointed against vacancies which were filled up in the first instance, but thereafter, became available again.

Learned counsel for the appellants states that he has no objection to the disposal of the instant appeals, in respect of the remaining appellants, in terms of the offer made by the State of U.P., as has been recorded in paragraphs 7 and 8 of the additional affidavit.

In view of the above, the instant appeals, with the consent of the parties, are disposed of in the aforesaid terms.

मा० सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1100/बीस-ई-5-2014-76/2009 दिनांक 07.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में बैच 1991 के प्रतीक्षा सूची से नियुक्त समीक्षा अधिकारियों को दिनांक 16.03.2005 तक नियुक्त कार्मिकों के पश्चात ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उक्त परिप्रेक्ष्य में रिट याचिका सं०- 32389/1997 योगेन्द्र कुमार पाल व अन्य बनाम राज्य एवं मा० उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अपील संख्या-256/1998 (नवीन संख्या-99/1999) "उत्तर प्रदेश राज्य योगेन्द्र कुमार पाल व अन्य" के अधीन नियुक्त एवं उत्तराखण्ड राज्य में तैनात समीक्षा अधिकारियों की कार्यालय ज्ञाप-975/XXXI(2)/2015, दिनांक 12 मई, 2015 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए प्रभावितों से 15 दिन के भीतर आपत्ति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। प्रश्नगत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों का साररूप में निस्तारण निम्नवत किया जा रहा है :-

क्र०सं०

आपत्ति का सार

आपत्ति के निस्तारण के सम्बंध में टिप्पणी

1

2

3

1

श्री देव सिंह, उप सचिव, श्री गिरीश चन्द्र जोशी, उपसचिव, श्री नन्दन बिष्ट, अनुसचिव एवं श्री देवेन्द्र सिंह, अनुसचिव द्वारा निम्न आपत्तियां व्यक्त की गयी है:-

इन अधिकारियों द्वारा दिनांक 12 मई, इस संदर्भ में स्पष्ट करना है दिनांक 24.10.2011 द्वारा 2015 के अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची के निर्धारण से पूर्व कोई आपत्ति नहीं किये गये, अपितु सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13

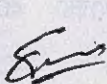

6/4/2015

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जुलाई, 2011 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में आपत्तियां कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.10.2011 आमंत्रित की गयी थी, तत्समय प्राप्त आपत्तियों के द्वारा निर्गत ज्येष्ठता सूची में निराकरण के उपरान्त ही 24 अक्टूबर, 2011 द्वारा अन्तिम उल्लिखित श्री विक्रम सिंह राणा, ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी थी। ज्येष्ठता सूची दिनांक उपसचिव, श्री राजेन्द्र पतियाल, 24.10.2011 में श्री विक्रम सिंह राणा, उपसचिव, श्री उपसचिव एवं ध्रुव मोहन सिंह राणा, राजेन्द्र पतियाल, उपसचिव एवं ध्रुव मोहन सिंह राणा, उपसचिव की ज्येष्ठता के सम्बंध में उपसचिव के ज्येष्ठता क्रमांक में उनके नाम के सम्मुख आपत्ति की गयी है।

मा0 उच्चतम/मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगें का उल्लेख किया गया है। चूंकि वर्तमान तक मा0 न्यायालयों से कोई अध्यावधिक आदेश प्राप्त नहीं हुए है, इस आधार पर प्रश्नगत कार्मिकों के वर्ष 2011 में निर्गत ज्येष्ठता में कोई संशोधन/परिवर्तन किया जाना तर्कसंगत नहीं है। अतः इस वर्ग की आपत्तियां अग्राह्य है।

2 श्री अहमद अली उपसचिव, श्री प्रताप सिंह शाही उपसचिव एवं श्री संजय सिंह टोलिया उपसचिव द्वारा निम्नवत आपत्तियां व्यक्त की गयी है:-

- (1) श्री अहमद अली उपसचिव, श्री प्रताप सिंह शाही उपसचिव द्वारा वर्ष 1991 संख्या-32389/97 श्री योगेन्द्र कुमार पाल बनाम राज्य व बैच के प्रतिक्षासूची से नियुक्त एवं अन्य एवं विशेष अपील संख्या-256/98 (नवीन संख्या उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत 05 -99/1999) में दिनांक 20.10.2007 को पारित अन्तिम कार्मिकों की प्रकरण को विस्तारपूर्वक आदेशों में 1991 बैच की प्रतीक्षा सूची से वर्ष 1999 में उल्लिखित किया गया है। पूर्व में दिये नियुक्त किये गये इन कार्मिकों की नियुक्ति को उचित गये प्रत्यावेदनों का भी उल्लेख किया नहीं माना है परन्तु प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध मा0 गया है। श्री अहमद अली व प्रताप उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 सिंह शाही साररूप में दिनांक 12 संख्या-14296-14297/2008 में पारित अन्तिम आदेश मई, 2015 के पत्र को निरस्त करने, दिनांक 3.2.2014 में पारित कार्मिकों की दीर्घकालीन 1991 की प्रतिक्षा सूची से चयनित सेवा व इनके आश्रितों की स्थिति के दृष्टिगत मानवीय कार्मिकों की सेवा समाप्त करने, श्री आधार पर इन कार्मिकों को सेवा में बनाये रखे जाने के विक्रम सिंह राणा, उपसचिव, श्री उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया राजेन्द्र पतियाल, उपसचिव एवं ध्रुव गया है। अतः इन कार्मिकों को सेवाओं से हटाये जाने मोहन सिंह राणा, उपसचिव के नाम सम्बंधी आपत्ति अग्राह्य है। श्री विक्रम सिंह राणा, वर्ष 2011 की ज्येष्ठता से हटाये जाने उपसचिव, श्री राजेन्द्र पतियाल, उपसचिव एवं ध्रुव मोहन

 d 

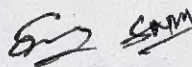

व आदि प्रश्नगत विषय से इतर तथ्य सिंह राणा, उपसचिव के संदर्भ में उक्त बिन्दु संख्या-1 उठाये गये हैं। स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

(2) श्री अहमद अली द्वारा यह भी इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि उ0प्र0 सरकार कथन किया गया है कि योगेन्द्र पाल द्वारा योगेन्द्र पाल की रिट याचिका-32389/97 में पारित विषयक रिट याचिका का उल्लेख श्री मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9.4.1998 के सापेक्ष श्याम सिंह, श्री ओंकार व श्री कृष्ण प्रेषित प्रस्तावों पर परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग सिंह के नियुक्ति आदेश में भी है उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा प्रवर वर्ग सहायक/अवर सहायक के पदों के सापेक्ष शासन को प्रेषित चयन संस्तुति सचिवालय प्रशासन इनके विरुद्ध कोई सहायक के पदों के सापेक्ष शासन को प्रेषित चयन संस्तुति कार्यवाही नहीं कर रहा है। विषयक पत्र दिनांक 14 मई, 1999 में श्री श्याम सिंह, श्री ओंकार व श्री कृष्ण सिंह के नाम उल्लिखित नहीं है। पुनः उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 08.08.2014 में श्री श्याम सिंह, श्री ओंकार व श्री कृष्ण सिंह के नाम नहीं है। अतः यह आपत्ति अग्राह्य है।

(3) श्री संजय टोलिया, उप सचिव इस सम्बंध में स्पष्ट करना है कि श्री टोलिया द्वारा ज्येष्ठता से इतर कथन करते हुए द्वारा ज्येष्ठता से इतर बिन्दुओं को उठाया गया है। अतः आरोप लगाया गया है कि शासन द्वारा आपत्ति अग्राह्य है। प्रकरण पर जानबूझ कर बिलम्ब किया जा रहा है।

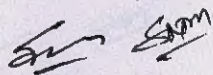
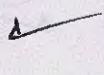
3 श्री ललित मोहन आर्य, संयुक्त सचिव श्री संजीव कुमार शर्मा, उपसचिव, श्री रावेन्द्र कुमार चौहान उपसचिव, श्री शैलेश कुमार पंत उपसचिव द्वारा निम्न आपत्तियों व्यक्त की गयी हैं:-

(1) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि रिट याचिका में योजित रिट याचिका संख्या-32389/97 में पारित मा0 उच्च न्यायालय सं0-32389 /97 "योगेन्द्र के आदेश दिनांक 09.04.1998 के अनुक्रम में कुमार पाल बनाम राज्य व राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग से अन्य" एवं विशेष अपील सं0 अभ्यर्थियों की संस्तुति उपलब्ध कराने का आग्रह "256/98(नवीन अपील सं0 किया गया। जिसके क्रम में परीक्षा नियंत्रक 99/ 1999)" में उक्त कार्मिक लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा प्रेषित न तो वादी थे एवं न प्रतिवादी प्रवर/अवर वर्ग सहायक के पदों के लिए चयन एवं न ही उक्त याचिका में संस्तुति पत्र दिनांक 14 मई, 1999 में इन उत्तराखण्ड राज्य प्रतिवादी था, कार्मिकों के नाम यथा क्रमांक संख्या-14 (श्री जिस कारण उक्त निर्णय इन संजीव कुमार शर्मा) क्रमांक संख्या-23 (श्री शैलेश कुमार पन्त) क्र0सं0-38 (श्री ललित मोहन आर्य) कार्मिकों पर लागू नहीं होता है। क्र0सं0 40 (श्री रावेन्द्र कुमार चौहान) नाम

उल्लिखित है और लोक सेवा आयोग के पत्र के प्रस्तर-02 में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि संस्तुतियों रिट याचिका संख्या-32389/1997 "योगेन्द्र कुमार पाल बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य" में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। इसी क्रम में सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-05 उ0प्र0 द्वारा इन कार्मिकों के नियुक्ति पत्रों में भी संख्या-32389/1997 "योगेन्द्र कुमार पाल बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य" तथा विशेष अपील संख्या-256/98 तथा रिट याचिका संख्या-7979/88 में होने वाले निर्णय के अधीन होने का उल्लेख किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि सचिवालय प्रशासन अनुभाग उ0प्र0 शासन के उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित पत्र संख्या-599 दिनांक 08.08.2014 से भी हो जाती है। उ0प्र0 सरकार के प्रश्नगत पत्र दिनांक 08.08.2014 के प्रस्तर-3 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 14.5.1999 की प्रति उपलब्ध कराते हुए यह स्पष्ट किया है कि प्रश्नगत कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्यरत है और इनके संदर्भ में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है। अतः प्रश्नगत आपत्ति तर्कहीन होने से अग्राह्य है।

- (2) कार्मिकों का यह भी कथन है सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-02 कि उन्हें सुनवाई का कोई के कार्यालय ज्ञाप सं0-975/XXXI(2)/2015, अवसर नहीं दिया गया तथा दिनांक 12 मई, 2015 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता दिनांक 02.05.2008 को अन्तिम सूची निर्गत कर प्रकरण में आपत्तियों आमंत्रित निर्णय लिये जाने से आज तक की गयी थी, जिस क्रम में इन कार्मिकों द्वारा की तिथि तक न तो मा0 उच्च आपत्तियाँ भी प्रस्तुत की गयी। जिसका निस्तारण न्यायालय के निर्णय को हस्तगत इस आदेश द्वारा किया जा रहा है। अतः यह

कराया गया है। अतः उच्च कहना कि इन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान न्यायालय के निर्णय को लागू नहीं किया गया, उचित नहीं है।

करना संविधान के

अनुच्छेद-226 का भी उल्लंघन

है एवं जब उक्त आदेश लागू

नहीं होता है तो इसके विरुद्ध

मा0 सर्वोच्च न्यायालय का

आदेश दिनांक 03.02.2014 उन

पर लागू करना संविधान का

उल्लंघन है।

(3) उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि उत्तर

मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03. प्रदेश सरकार द्वारा 27.08.2013 को मा0 उच्चतम

02.2014 को, जो निर्णय पारित न्यायालय में योजित प्रतिशपथ-पत्र में इन

किया गया था, वह उत्तर प्रदेश कार्मिकों को इनकी मा0 उच्च न्यायालय के

शासन द्वारा दिनांक 27.08.2013 आदेश के उपरान्त सेवा में काफी लम्बी अवधि,

को मा0 न्यायालय में योजित इन कार्मिकों के आश्रितों आदि पक्षों के दृष्टिगत

अतिरिक्त प्रतिशपथ पत्र के मानवीय आधार पर इन कार्मिकों को सेवा में

आधार पर पारित किया गया। बनाये रखने का अनुरोध किया गया है। यह

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पारित अनुरोध इन कार्मिकों के प्रतिकूल नहीं है। अपितु

उक्त प्रतिशपथ पत्र दोनों पक्षों मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.

की उभय सहमति के आधार पर 2007, जिसके द्वारा इनकी नियुक्ति को उचित

दाखिल किया गया, इसमें उक्त नहीं माना है, के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा

कार्मिकों को सुनवाई का अवसर सकारात्मक पक्ष मा0 उच्चतम न्यायालय में रखा

नहीं दिया गया। अतः यह कहा जाना कि उ0प्र0 के

प्रतिशपथ-पत्र के आधार पर लिये गये निर्णय

उन पर लागू नहीं होता है तर्कसंगत नहीं है।

अतः प्रश्नगत आपत्ति अग्राह्य है।

(4) उक्त कार्मिकों द्वारा यह भी इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि

अवगत कराया जा रहा है कि प्रश्नगत विशेष अपील संख्या-99/1999 उ0प्र0

मा0 उच्चतम न्यायालय के राज्य व अन्य बनाम योगेन्द्र कुमार पाल व अन्य

आदेश दिनांक 03.02.2014 के को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया

प्रस्तर-08 में उल्लिखित है कि गया और दिनांक 30.10.2007 को पारित अन्तिम

28. वादी एवं 11 जोकि वादी आदेश में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका नहीं थे, का ही उल्लेख है। संख्या-32389/97 में पारित आदेश दिनांक 09. उक्त 39 कार्मिकों (मा0 उच्चतम 04.1998 को Set aside करते हुए रिट याचिका न्यायालय के निर्णय में संख्या-32389/97 "योगेन्द्र कुमार पाल बनाम उल्लिखित) में उक्त 04 कार्मिकों उ0प्र0 राज्य व अन्य" को खारिज कर दिया गया। का नाम सम्मिलित नहीं है। अतः मा0 उच्च न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक उक्त 05 कार्मिकों पर मा0 30.10.2007 के विरुद्ध श्री योगेन्द्र कुमार पाल व उच्चतम न्यायालय का निर्णय अन्य द्वारा रिकाल प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2014 लागू नहीं संख्या-265023/2007 योजित की गयी, जिसमें है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2.5.2008 को विस्तृत निर्णय पारित करते हुए रिकाल प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के प्रश्नगत आदेशों दिनांक 30.10.2007 एवं दिनांक 2.05.2008 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-14296/97/2008 "योगेन्द्र कुमार पाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य" तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-14791-92/2008 "लाल बहादुर सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य" योजित की गयी थी। इन्ही विशेष अनुज्ञा याचिकाओं को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 03.2.2014 के आदेश द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित की गयी है। अतः यह कहना यह उन पर लागू नहीं होता, तर्कहीन है। अतः प्रश्नगत आपत्ति अग्राह्य है।

(5) उक्त कार्मिकों द्वारा यह भी कहा गया है कि सचिवालय प्रशासन विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-14296-97/2008 में (अधिष्ठान) अनुभाग-02 के पत्र मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2014 दिनांक 19.04.2012 द्वारा को अन्तिम निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः कार्मिकों को मा0 उच्चतम इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर कोई टिप्पणी न्यायालय में योजित विशेष किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रश्नगत आपत्ति अनुज्ञा याचिका सं0 अग्राह्य है।

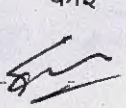
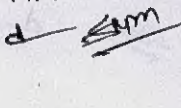
14296-14297/2008 के



सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया। तत्क्रम में, उनके द्वारा उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में ईम्पलीड करने की अनुमति मांगी गयी किन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त कार्मिकों को ईम्पलीड करने की अनुमति नहीं दी गयी एवं न ही विशेष अनुज्ञा याचिका प्राप्त करने की अनुमति दी गयी, इस आधार पर इन कार्मिकों का यह कथन है कि उक्त के कारण उन पर मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.02.2014 लागू नहीं होता।

- (6) भारत सरकार के आदेश उ0प्र0 पुनर्गठन की धारा-73/74 के अनुसार नियत दिनांक 09.11.2000 से पूर्व की सेवाओं में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः यह उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 का उल्लंघन है।
- इस सन्दर्भ में स्पष्ट करना है कि इन कार्मिकों की नियुक्ति मा0 न्यायालय में लम्बित अपील में होने वाले निर्णय के अधीन की गयी थी। प्रश्नगत निर्णय को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 30.10.2007 को अपास्त कर दिया है। मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-14296-97/2008 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2014 के अनुपालन में इन कार्मिकों की ज्येष्ठता संशोधित की जा रही है। अतः प्रश्नगत आपत्ति अग्राह्य है।

- (7) प्रश्नगत कार्मिकों द्वारा यह भी कहा गया है कि उ0प्र0 राज्य व उत्तराखण्ड राज्य दोनों की परिस्थितियों में अन्तर है। उ0प्र0 में 2001 बैच द्वारा सीधी भर्ती में नियुक्ति हुयी है, जबकि 2001 बैच का कोई कार्मिक
- इन कार्मिकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में वर्ष 1999 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-संख्या-32389/97 एवं विशेष अपील संख्या-99/1999 के तहत की गयी थी जिसे मा0 न्यायालय द्वारा उचित नहीं माना गया। अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2014 में उल्लिखित तिथि से ही ज्येष्ठता दिया जाना

उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत बाध्यकारी है।
नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में
सीधी भर्ती से चयन 2004 बैच
द्वारा की गयी है तथा संविलियन
नियमावली, 2002 के अन्तर्गत
अन्य विभागों के कार्मिक भी
सचिवालय में संविलियन कर
लिये गये हैं। अतः दिनांक 16.
03.2005 के पश्चात इन्हें
ज्येष्ठता में रखा जाना उचित
नहीं है।

4- अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या-975/XXXI(2)/2015 दिनांक 12 मई, 2015 द्वारा
निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बंध में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण
उपरोक्तानुसार करते हुए एतद्वारा प्रश्नगत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को निम्नानुसार
अन्तिम किया जाता है :-

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 में ज्येष्ठता क्रमांक	मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2014 के अनुपालन में अन्तिम रूप से निर्धारित ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम
30	259 "ए"	श्री संजीव कुमार शर्मा
31	259 "बी"	श्री शैलेश कुमार पंत
36	259 "सी"	श्री रावेन्द्र कुमार चौहान
38	259 "डी"	श्री ललित मोहन आर्य

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्तानुसार इन कार्मिकों की ज्येष्ठता
अन्तिम रूप से निर्धारित हो जाने के परिणामस्वरूप इनके द्वारा पूर्व में धारित ज्येष्ठता
क्रमांक-30, 31, 36 एवं 38 को अब रिक्त समझा जाय।

4- कार्यालय ज्ञाप संख्या-2549/XXXI(2)2011 दिनांक 24.10.2011 को उपरोक्त
सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त कार्यालय ज्ञाप की शेष शर्तें/प्राविधान
यथावत् रहेंगे।

पी0एस0 जंगपांगी
सचिव

संख्या-1506(1)/XXXI(2)/2015-90 (विविध)/2011, तददिनांकित
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) प्रमुख सचिव/सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

- 2) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5) महा निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6) निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7) सम्बंधित कार्मिक।
- 8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर सचिव।

क्र.सं.	विवरण	प्रतिपाद्य
1	प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2	प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3	स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।	स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4	महा निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।	महा निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5	निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), सचिवालय परिसर, देहरादून।	निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), सचिवालय परिसर, देहरादून।
6	सम्बंधित कार्मिक।	सम्बंधित कार्मिक।
7	गार्ड फाइल।	गार्ड फाइल।